(d) whether it is fact that loan from the I.M.F. under the stand by and earlier arrangements has been used to effectively build up country's foreign exchange reserve ; and

(e) if so, percentage share of the above in the country's foreign exchange reserve during the above period ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) and (b) the foreign exchange rserves of the country (excluding gold and SDRs.) stood at US $ 15,074 million as at the end of March 1994, US $ 6434 million at the end of March 1993, US $ 5631 at the end of March, 1992 and US $ 2236 million at the end of March, 1991.

(c) the increase in reserves (excluding gold and SDRs.) during the fiscal 1993-94 by US $ 8,640 million is because of a number of current and capital transactions. Exports posted a higher growth of around 20 per cent as per the customs data, while there was a very sharp deceleration in import growth. Inflows in the form of foreign investment (including Euro-convertible bonds) amounted to US $ 4.5 billion. There was an estimated inflow of US $ 1062 million under non-resident deposit schemes. Reliance on external aid has gradually declined and for both 1992-93 and 1993-94 repayment of principal and interest were more than the aid disbursed.

(d) and (e) Drawals from the IMF under the contingency and compensatory financing facility and the stand by arrangement accrued to the country's foreign exchange reserves in the form of foreign currencies as well as SDRs. It is, therefore, appropriate to compare the outstanding credits under the two facilities from the IMF with the level of foreign exchange reserves including SDR (excluding gold). This is shown below :

(US $ Millian)

	March 1991	March 1992	March 1993	March 1994
1. Net Drawals from the IMF (outstanding Credits)	2623	3451	4799	5040
Foreign exchange Reserves (including SDRs lent excluding gold)	2338	5721	6452	15176
(1) as proportion to	112	60	74	33
(2) in per cent				

सरकारी संव्यवहार हेतु प्राधिकृत बैंक

4436. श्री कैलाश नारायण सारंग : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न राज्यों के शासकीय कोष का कार्य करने के लिए किन-किन बैंकों को प्राधिकृत किया गया है ;

(ख) राज्यों के जिन जिलों/तहसीलों में इन बैंकों की शाखाएं नहीं हैं वहां राज्यों के शासकीय कोष का कार्य करने की क्या व्यवस्था है ; और

(ग) क्या विभिन्न राज्यों के जिन स्थानों पर गैर बैंकिंग उप कोषालय कार्यरत हैं, उनको पूरी तरह से समाप्त कर विभिन्न बैंकों के माध्यम से शासकीय कोष का कार्य किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और यह योजना कब तक कार्यान्वित कर दी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न राज्यों के कोषालयों/उप कोषालयों से संबंधित सरकारी कार्य को करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, इसके साथ अनुषंगी बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया हुआ है ।

(ख) जिन जिलों/तहसीलों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कोई शाखा नहीं है, उनमें ऐसे केन्द्रों पर कार्य कर रहे सरकारी कोषालय/उप कोषालय सरकारी प्राप्ति एवं भुगतान का काम करते हैं ।

(ग) गैर-बैंकिंग कोषालयों/उप कोषालयों को परिवर्तित करने का निर्णय संबंधित राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है । यह निर्णय उस केन्द्र में सरकारी क्षेत्र के बैंक की उपस्थिति, आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता आदि बातों

को ध्यान में रख कर किया जाता है । कोषागारों/उप कोषागारों के नकद कारबार को संबंधित केन्द्रों में कार्य कर रही सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में स्थानांतरित करने के लिए राज्य सरकार(रों) से प्राप्त अनुरोधों पर संबंधित बैंकों के साथ परामर्श करके भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जाता है।

सरलीकृत आयकर कानून

4427. **श्री राजवंती :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरलीकृत नया आयकर कानून बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक अधिनियमित कर दिया जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मामले पर भविष्य में विचार करने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) आयकर कानून का सरलीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

विदेशी ऋणों का भुगतान

4428. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार मूलधन तथा इस पर ब्याज सहित प्रति वर्ष चुकता किए जा रहे विदेशी ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(ख) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार, भारत पर विदेशी ऋण की कुल कितनी धनराशि थी और इसे चुकता करने की क्या प्रक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) मूलधन की वापसी/अदायगी और विदेशी ऋण पर ब्याज का भुगतान जिसमें रक्षा ऋण और अनिवासी भारतीय जमा राशियां शामिल हैं, क्रमशः 1990-91 में 4.46 बिलियन अमरीकी डालर और 3.67 बिलियन अमरीकी डालर, 1991-92 में 4.53 बिलियन अमरीकी डालर और 3.68 बिलियन अमरीकी डालर और, 1992-93 में 4.45 बिलियन अमरीकी डालर और 3.72 बिलियन अमरीकी डालर था । 1993-94 के दौरान मूलधन की वापसी / अदायगी की राशि और ब्याज का भुगतान 4.55 बिलियन अमरीकी डालर और 3.71 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है ।

(ख) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश पर कुल बकाया विदेशी ऋण, जिसमें रक्षा ऋण और अनिवासी भारतीय जमा राशियां भी शामिल हैं, सितम्बर, 1993 के अंत तक 90.386 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है । विदेशी ऋणों की वापसी / अदायगी दाता एजेंसियों के साथ परस्पर सहमति से प्रत्येक ऋण समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार निर्धारित तिथियों पर ही की जाती है।

केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में भर्ती पर प्रतिबंध

4429. **श्री एस० आस्टिन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में विभिन्न पदों/श्रेणियों के अन्तर्गत नई भर्ती किये जाने पर रोक लगाई गई है;

(ख) यदि हां, तो कब से रोक लगाई गयी है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस प्रतिबन्ध को हटाने का विचार रखती है ;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भर्ती पर सामान्य तौर पर कोई रोक नहीं है । तथापि, मितव्ययिता बरतने सम्बन्धी उपायों के एक भाग के रूप में मई, 1993 में इस आशय के अनुदेश जारी किए गए थे कि उन पदों को जो एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए रिक्त पड़े हुए हैं, समाप्त हुआ समझा जाएगा और यदि आवश्यकता महसूस होती है तो पदों के सृजन की निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद उन्हें पुनः सृजित किया जा सकता है।

(ख) से (ङ) : प्रश्न नहीं उठते ।

Regional Rural Banks in Tamil Nadu

4430. SHRI S. AUSTIN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the numbers and locations of the Regional Rural Banks functioning in Tamil Nadu ;

(b) the main objectives of these banks and the extent to which these objectives have been achieved during the last two years ;

(c) whether some of these banks are facing financial crisis ;

(d) if so, the reasons therefor ; and

(e) the measures taken by Government to improve the performance of the above banks ?